बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 80 ● नई दिल्ली ● सोमवार 05 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रियंका गांधी की करेंगे मदद

नई दिल्ली। कांग्रेस ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत स्क्रीनिंग कमेटियां गठित की हैं. असम के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी गई है. इसी कमेटी में सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सदस्य बनाया गया है, जो असम में संगठन और उम्मीदवार चयन से जुड़े कामों में प्रियंका गांधी की मदद करेंगे. यह फैसला पार्टी की रणनीतिक तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और सही उम्मीदवारों का चयन करना है. असम के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा चेयरपर्सन हैं, जबकि सदस्य के तौर पर सप्तगिरी शंकर उलाका, इमरान मसूद और डॉ. सिरिवेला प्रसाद को शामिल किया गया है.

प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी, पिछली बार जीत-हार के बीच वोट का कम अंतर, इस बार कितना अवसर

नई दिल्ली । देश के कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असमऔर पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है और स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है.

ऐसा हर बार होता है और यह रूटीन प्रक्रिया है. हालांकि इस बार प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष होंगी. ऐसा पहली बार है जब गांधी परिवार से किसी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. इस कमेटी का काम होता है विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का चयन करना. राज्य की हर विधानसभा से जो भी नाम आएंगे, उसमें से सबसे बेहतर उम्मीदवार का चयन कर उसे एक, दो, तीन की वरीयता में डाल कर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखना. उम्मीदवारों के इस पैनल पर अंतिम फैसला कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति लेती है. असम की इस स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ दो अन्य सदस्यों के अलावा इमरान मसूद भी हैं, जो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं. हालांकि सबसे दिलचस्प बात ये है कि इन्हीं इमरान मसूद ने ठीक दस दिन पहले प्रियंका गांधी को लेकर एक बयान दिया था जो काफी सुर्खियों में रहा था. इमरान मसूद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के सवाल पर कहा था कि बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी की तरह

बांग्लादेश को जवाब देंगी, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं. इमरान मसूद के इस बयान पर काफी बवाल हुआ था और इसके कई मायने निकाले गए थे. अब इमरान मसूद को प्रियंका गांधी की टीम में ही जगह दी गई है.

प्रियंका गांधी को क्यों दिया असम का जिम्मा

अब सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी को असम के स्क्रीनिंग कमेटी का जिम्मा क्यों दिया गया है और क्या इसके पीछे भी सोची समझी रणनीति है.

असम के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई भी युवा हैं, उनके पिता तरुण गोगोई कई बार असम के मुख्यमंत्री रहे और 10 जनपथ के करीबी थे. गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं यानी राहुल गांधी के बाद कांग्रेस संसदीय दल में उनकी हैसियत नंबर 2 की है. गौरव गोगोई, सचिन पायलट, जीतू पटवारी जैसे नेताओं को कांग्रेस की नई पीढ़ी के नेताओं के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में प्रियंका गांधी को गौरव गोगोई के मददगार के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में सवाल ये भी है कि असम ही क्यों, क्या यहां कांग्रेस के लिए कोई चांस है, क्या गौरव गोगोई हिमंता बिस्वा सरमा को चुनौती दे पाएंगे. बहुत सारे जानकार मानते हैं कि इस चुनाव में तो संभव नहीं हैं. हां, गौरव गोगोई लगे रहे तो पांच साल बाद संभव है. हालांकि असम के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं. दरअसल, वहां चुनाव गठबंधन के बीच होता है, जैसे पिछली बार एनडीए को 126 विधानसभा सीटों में 75 सीटें मिली थी और कांग्रेस गठबंधन वाली महाजोत को 50 सीट. हालांकि यदि आप वोटों के प्रतिशत को देखें तो एनडीए को 43.9 फीसदी वोट मिले थे, जबकि महाजोत को 42.3 फीसदी यानी अंतर सिर्फ 1.6 फीसदी वोटों का ही था.

जहांगीरपुरी में दो युवकों पर चाकू से कई बार हमला किया गया, दोनों घायल

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चार लोगों ने कथित तौर पर कई बार चाकू से वार करके 18 वर्षीय दो युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, जहांगीरपुरी पुलिस थाने को दोपहर करीब 2.55 बजे पीसीआर पर जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें जहांगीरपुरी के के ब्लॉक के पास चाकूबाजी की घटना की सूचना दी गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, मौके पर पहुंचने पर पुलिस को अंशु और विमल नाम के दो घायल व्यक्ति मिले, दोनों की उम्र 18 वर्ष थी। अंशु के दाहिने हाथ पर चाकू से वार किए गए थे, जबकि विमल को कई जगह चाकू के घाव लगे थे। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और बाद में आगे के इलाज के लिए लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह हमला के ब्लॉक में चार लोगों द्वारा बिना किसी उकसावे के किया गया था। पूछताछ के दौरान घायलों ने पुलिस को बताया कि हमलावर उनके पास आए और पूछा कि क्या वे साहिल नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं। जब पीड़ितों ने नहीं में जवाब दिया, तो आरोपियों ने आगे पूछा कि क्या वे के ब्लॉक के निवासी हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ ही देर बाद, हमलावरों ने कथित तौर पर धारदार हथियार निकाले और दोनों पर वार करके उन्हें घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि अंशु का बयान तब दर्ज किया गया जब उसे बयान देने के लिए स्वस्थ घोषित किया गया। उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान और उन्हें ढूंढने के लिए कई टीम गठित की गई हैं और हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आगे की जांच जारी है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और शीतलहर का डबल अटैक, कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी, बहुत खराब हुई हवा

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ-साथ प्रदूषण का कहर जारी है। रविवार सुबह दिल्लीवासी ठंडी, बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के बीच उठे। कोहरे के कारण शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 248 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि, शहर के कई हॉटस्पॉट्स पर हालात इससे कहीं ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। राजधानी के मुख्य मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आनंद विहार (350), रोहिणी (361), चांदनी चौक (355) और मुंडका (329) जैसे इलाकों में सांस लेना दूभर हो गया है। इसके विपरीत, NSIT द्वारका और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में हवा थोड़ी बेहतर रही, जहां एक्यूआई 177 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई है। प्रदूषण और स्मॉग की इस धुंध के बावजूद, इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां ज़ोर-शोर से जारी हैं। जवानों का अभ्यास और अन्य तैयारियां कोहरे के बीच भी थमी नहीं हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। ठंड और धुंध का यह सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर और मध्य भारत के लिए भी मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आने और घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पहाड़ी रायों की बात करें तो 5 और 6 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 6 जनवरी को बारिश के आसार हैं। पहाड़ों पर होने वाली इस हलचल का सीधा असर मैदानी इलाकों की ठंड पर पड़ेगा।

दिल्ली में 5-6 जनवरी को कई इलाकों में नहीं आएगा पानी, पहले ही कर लें स्टोर; जल बोर्ड ने वजह बताई

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र पर बड़े रखरखाव कार्य के कारण दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति बाधित होने की सूचना जारी की है। यह बाधा 5 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे से शुरू होकर 16 घंटे तक रहेगी, जिससे 5 जनवरी की शाम और 6 जनवरी की सुबह जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी। बोर्ड ने इससे होने वाली असुविधा पर गहरा खेद व्यक्त किया है। प्रभावित क्षेत्रों में दक्षिण दिल्ली के कई कमांड क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कैलाश नगर, गांधी नगर, भर्ती नगर, रविंद्र नगर, देवली, अम्बेडकर नगर, बादरपुर, जैतपुर, नेहरू जगह के पास ढलाईन पार्क, अशोका पार्क के पास मुख्य सड़क, लायंस हॉस्पिटल, खिजराबाद गांव, मीराबाई पॉलिटेक्निक, एसपीए हॉस्टल्स, एनडीएमसी और आसपास के इलाके शामिल हैं। अन्य क्षेत्रों में सीडब्ल्यूजी गांव, पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बतला हाउस, डीईएसयू कॉलोनी, सिद्धार्थ एन्क्लेव, खान मार्केट, काका नगर, अलीगंज, जोर बाग, लोधी कॉलोनी फ्लैट्स, निजामुद्दीन, प्रगति विहार, दक्षिणपुरी, शाहपुर जाट, साउथ एक्सटेंशन, कोटला मुबारकपुर, मुबारकपुर, सेवा नगर, लाजपत नगर, भोगल, सराय काले खान, अपोलो हॉस्पिटल, सरिता विहार, जसोला, मदनपुर खादर, जीके साउथ, छतरपुर, श्रीनिवासपुरी, अमर कॉलोनी, मालवीय नगर आदि शामिल हैं। जल बोर्ड ने लोगों से पर्याप्त पानी पहले से स्टोर करने की अपील की है। आपात स्थिति में पानी की जरूरत पड़ने पर टैंकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए विभिन्न जल नियंत्रण कक्षों से संपर्क किया जा सकता है।

आपात स्थिति में यहां करें संपर्क

संपर्क नंबर इस प्रकार हैं- मंडावली - 22727812, ग्रेटर कैलाश - 29234746, गिरी नगर - 26473720, छतरपुर (कुतुब) - 65437020, आई.पी./स्टेशन - 23370911, 23378761, आर.के. पुरम - 26193218, जल सदन - 29819035, 29814106, वसंत कुंज - 26137216, सेंट्रल कंट्रोल रूम - 1916, 23538495। आपातकालीन जल टैंकर के लिए 1916 पर कॉल करें।

शाहदरा में सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड, बुजुर्ग दंपति की हत्या; अलग-अलग कमरे में मिले शव

नई दिल्ली । दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड ने इलाके में दहशत फैला दी है। राम नगर एक्सटेंशन में स्थित एक मकान के तीसरे मंजिल पर 75 वर्षीय विरेंद्र कुमार बंसल (रिटायर्ड टीचर) और उनकी 65 वर्षीय पत्नी परवेश बंसल (गृहिणी) के शव अलग-अलग कमरों में पड़े मिले। पुलिस को यह जानकारी आधी रात करीब 12:30 बजे पीसीआर कॉल से मिली। कॉल करने वाले दंपति के बेटे वैभव बंसल ने बताया कि उनके माता-पिता बेहोश पड़े हैं और शायद मर चुके हैं। सूचना मिलते ही एमएस पार्क थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वैभव ने पुलिस को बताया कि किसी ने उनके माता-पिता की हत्या कर दी है। निरीक्षण में विरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान मिले। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फोटोग्राफी की। पुलिस प्रारंभिक जांच में लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर रही है, हालांकि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। यह घटना इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। पुलिस टीमों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी है।

लोकसभा में निर्विरोध चुनाव अत्यंत दुर्लभ

वैश्विक स्तर पर भारत, जिसे गर्व से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहाँ चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जनता की सामूहिक चेतना, असहमति, सहमति और विश्वास का संवैधानिक माध्यम है। लोकतंत्र की आत्मा इस सिद्धांत पर टिकी है कि सत्ता जनता से निकलती है, जनता द्वारा संचालित होती है और जनता के हित में कार्य करती है। ऐसे में यह प्रश्न अत्यंत गंभीर हो जाता है कि जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार मैदान में रह जाता है और वह निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, तब मतदाता की इच्छा, असहमति और अभिव्यक्ति का क्या होता है? विशेषकर तब, जब वहीं मतदाता नोटा (नन ऑफ द अबव) जैसे विकल्प के माध्यम से यह कहने का संवैधानिक अधिकार रखता है कि उसे कोई भी उम्मीदवार स्वीकार नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2) स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने पद हैं, उतने ही उम्मीदवार शेष रह जाएँ, तो निर्वाचन अधिकारी उन्हें बिना मतदान के निर्वाचित घोषित करेगा। इसी प्रकार, चुनाव संचालन नियम, 1961 का नियम 11, तथा फॉर्म 21 और 21बी, निर्विरोध चुनाव के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को वैधानिक रूप देते हैं।कानूनी दृष्टि से यह व्यवस्था प्रशासनिक सरलता और संसाधनों की बचत के उद्देश्य से बनाई गई थी। किंतु आज, जब लोकतंत्र केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि जन- भागीदारी और जन-सहमति का प्रतीक बन चुका है,तब यह प्रावधान अपने औचित्य पर पुनर्विचार की माँग करता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारतीय संविधान केवल शासन की संरचना नहीं,बल्कि एक जीवंत लोकतांत्रिक दस्तावेज है,जिसकी आत्मा जन -सहमति, जन-भागीदारी और जन- उत्तरदायित्व में निहित है। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने का आधार केवल चुनावों की संख्या नहीं, बल्कि यह तथ्य है कि यहाँ प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक भागीदारी और अभिव्यक्ति का समान अधिकार प्राप्त है। ऐसे में जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है और मतदाताओं को मतदान का अवसर ही नहीं दिया जाता, तब यह प्रश्न उत्पन्नस्वाभाविक है कि क्या यह व्यवस्था संविधान की मूल भावना के अनुरूप है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों की संवैधानिक रूपरेखा निर्धारित की गई है। यद्यपि मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है,किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने समय- समय पर यह स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है। लोकतंत्र में चुनाव का अर्थ केवल प्रतिनिधि चुनना नहीं है, बल्कि यह नागरिक की सहमति और असहमति दोनों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यदि किसी नागरिक को केवल स्वीकृति का अवसर मिले, परंतु अस्वीकृति का नहीं, तो लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। साथियों बात अगर हम नोटा, असहमति का संवैधानिक अधिकार इसको समझने की करें तो, भारत में नोटा विकल्प को 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले (पीयूसीएल बनाम भारत संघ) के माध्यम से मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य स्पष्ट था,मतदाता को यह अधिकार देना कि वह चुनाव में भाग तो ले,परंतु किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार न करे।नोटा लोकतंत्र में नकारात्मक सहमति (नेगेटिव कंसेंट) का प्रतीक है। यह वोटर की वह चुप आवाज है जो कहती है,मैं चुनाव प्रणाली में विश्वास करता हूँ, लेकिन उम्मीदवारों में नहीं। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब चुनाव ही नहीं होता, तो नोटा का अस्तित्व किस लिए? यह विकल्प मतदाता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1)(a)) से जुड़ा हुआ है। नोटा का उद्देश्य यह था कि नागरिक यह कह सके,मैं चुनाव प्रणाली में विश्वास करता हूं, किंतु प्रस्तुत विकल्पों से संतुष्ट नहीं हूं। नोटा, संविधान के इस मूल सिद्धांत का मूर्त रूप देता है, जिसमें नागरिक को केवल शासक चुनने का नहीं, बल्कि शासन के स्वरूप पर प्रश्न उठाने का भी अधिकार प्राप्त है। साथियों बात अगर हम निर्विरोध चुनाव धारा 53(2) और संवैधानिक द्वंद्व इसको गहराई से समझने की करें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम1951 की धारा 53 (2)के अनुसार यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उतने ही उम्मीदवार रह जाएँ जितनी सीटें है, तो निर्वाचन अधिकारी उन्हें बिना मतदान के निर्वाचित घोषित कर देगा। चुनाव संचालन नियम, 1961 का नियम 11 तथा फॉर्म 21/21 बी इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते है। यह प्रावधान प्रशासनिक सुविधा और व्यावहारिकता के लिए बनाया गया था, किंतु आज के संवैधानिक परिवेश में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह व्यवस्था- जन-सहमति राजनीतिक समानताऔर लोकतांत्रिक नैतिकता के सिद्धांतों के अनुरूप है? संविधान का मूल दर्शन यह है कि सत्ता जनता की इच्छा से उत्पन्न होती है। जब निर्विरोध चुनाव में मतदाता को मतदान का अवसर ही नहीं दिया जाता, तब उसकी इच्छा चाहे वह समर्थन की हो या विरोध की संवैधानिक रूप से अदृश्य बना दी जाती है। यह स्थिति लोकतंत्र को जनता की सरकार से कानून द्वारा थोपी गई सरकार की ओर ले जाती है, जो संवैधानिक नैतिकता के बिल्कुल विपरीत है। साथियों बात अगर हम एक उम्मीदवार, शून्य विकल्प- क्या यह लोकतंत्र है? इसको समझने की करें तो,जब किसी सीट पर केवल एक उम्मीदवार बचता है और उसे निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया जाता है, तो मतदाता के सामने कोई विकल्प नहीं रह जाता। न समर्थन का, न विरोध का। यह स्थिति लोकतंत्र के मूल सिद्धांत,चॉइस (चयन) को निष्प्रभावी बना देती है। यदि मतदाताओं का बड़ा वर्ग यह मानता है कि वह उम्मीदवार जनहित का प्रतिनिधित्व नहीं करता,फिर भी कानून उसे प्रतिनिधि बना देता है। यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि वैधानिक एकाधिकार की स्थिति बन जाती है। साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट में उठा सवाल नोटा बनाम निर्विरोध जीत इसको समझने की करें तो, इसी संवैधानिक द्वंद्व को लेकर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53 (2) और चुनाव संचालन नियम, 1961 को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की कि यह एक बहुत रोचक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। पीठ ने यह भी पूछा कि, क्या केवल एक उम्मीदवार वाले चुनावों में मतदाताओं को नोटा का विकल्प नहीं दिया जा सकता? यह टिप्पणी अपने आप में इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका भी इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक कसौटी पर परखने को तैयार है।सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि इस विषय पर पहले सरकार से संपर्क करना उचित होगा। न्यायालय ने भी याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि यदि सरकार इस मुद्दे पर विचार नहीं करती,तो पुनः अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण संविधान के शक्ति संतुलन सिद्धांत को दर्शाता है,जहाँ विधायी सुधार पहले संसद से अपेक्षित है और न्यायपालिका अंतिम संरक्षक कीभूमिका में है। चुनाव आयोग का पक्ष- दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि लोकसभा में निर्विरोध चुनाव अत्यंत दुर्लभ है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार1991 से अब तक केवल एक निर्विरोध लोकसभा चुनाव,1971 से 2025 तक कुल छह,1951 से अब तक कुल 20 आम चुनावों में केवल नौ निर्विरोध चुनाव,आँकड़े भले ही कम हैं,परंतु लोकतंत्र में सिद्धांतों का मूल्य आँकड़ों से अधिक होता है। एक भी ऐसा मामला जहाँ मतदाता की इच्छा दबे, वह पूरे लोकतांत्रिक ढाँचे पर ही एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। साथियों बात अगर हम नोटा को उम्मीदवार मानने की बहस को सटीकता से समझने की करें तो चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि नोटा को निर्विरोध चुनावों में उम्मीदवार मानना वर्तमान कानून के अंतर्गत संभव नहीं है। इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 में विधायी संशोधन आवश्यक होंगे। यह स्वीकारोक्ति स्वयं यह दर्शाती है कि समस्या वैधानिक है, संवैधानिक नहीं,और इसका समाधान संसद के पास है। - न्यायालय की नैतिक टिप्पणी भी है कि नोटा आक्रोश का प्रतीक, पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि नोटा तभी प्रभावी होता है जब मतदाताओं में किसी उम्मीदवार के प्रति गंभीर आक्रोश हो।चुनाव आयोग को भी स्पष्ट करना होगा कि यदि इतना आक्रोश है, तो मतदाता स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा कर सकते है। किंतु यह तर्क व्यावहारिक यथार्थ से टकराता है, क्योंकि स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा करना संसाधन, सुरक्षा और राजनीतिक जोखिम से जुड़ा विषय है, जो हर नागरिक के लिए संभव नहीं। साथियों बात अगर हम स्थानीय निकायों में निर्विरोध चुनावअसली खतरे की घंटी,इसको समझने की करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के सांसद ने संसद में यह मुद्दा उठाया कि महाराष्ट्र के हालिया नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी के 25 से अधिक उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जिनमें परिवारवाद की स्पष्ट छाया दिखती है।स्थानीय निकाय लोकतंत्र की नींव होते है। यदि वहीं से निर्विरोध और वंशवादी प्रतिनिधित्व पनपने लगे, तो यह लोकतंत्र की सेहत पर गंभीर प्रभाव डालता है। साथियों बात अगर हम साम, दाम, दंड, भेद निर्विरोध चुनावों की स्याह परछाईं इसको समझने की करें तो नोटा समर्थक मतदाताओं का मानना है कि निर्विरोध चुनाव प्रायः स्वाभाविक नहीं होते। इसके पीछे धनबल दबाव धमकी, सौदेबाजी, पारिवारिक जैसे कारक सक्रिय रहते है। कई बार उम्मीदवारों से नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे जनता के सामने विकल्प ही समाप्त हो जाए।नामांकन आज कानून उम्मीदवार को नामांकन वापस लेने की अनुमति देता है। किंतु यदि इसी प्रावधान का दुरुपयोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, तो यह समय है कि कानून में संशोधन किया जाए।एक प्रस्ताव यह हो सकता है कि,एक बार वैध नामांकन भरने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सके, या कम से कम निर्विरोध स्थिति बनने से रोकने हेतु सख्त शर्तें लागू हों। यह सुधार लोकतंत्र में विकल्प की अनिवार्यता को सुनिश्चित करेगा।संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है। यदि उम्मीदवारों को दबाव या धनबल के माध्यम से नामांकन वापस लेने के लिए विवश किया जाता है, तो यह राजनीतिक समानता,निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र चुनाव तीनों का उल्लंघन है।आज नामांकन वापसी की अनुमति लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर दी जाती है। किंतु यदि यही स्वतंत्रता लोकतंत्र को विकल्प हीन बना दे, तो यह संवैधानिक उद्देश्य से विचलन है।ऐसे में यह विचार आवश्यक है कि निर्विरोध स्थिति बनने से पहले नामांकन वापसी पर सख्त शर्तें हों या नामांकन वापसी को सीमित किया जाए। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य-दुनियाँ क्या करती है? इसको समझने की करें तो, कई लोकतांत्रिक देशों में,एकल उम्मीदवार के विरुद्ध भी अनिवार्य मतदान,न्यूनतम वोट प्रतिशत की शर्त,रि -इलेक्शन का प्रावधान,जैसे उपाय मौजूद है।भारत जो लोकतांत्रिक आदर्शों का वैश्विक प्रवक्ता है,ऐसे परिपक्व लोकतंत्र से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वह प्रक्रिया से आगे बढ़कर भावना को समझे। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि लोकतंत्र प्रक्रिया नहीं, जन-सहमति है,निर्विरोध चुनाव वैधानिक हो सकते है,परंतु हर वैधानिक चीज लोकतांत्रिक हो,यह आवश्यक नहीं।

सम्पादकीय...

सरकारें अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती हैं

मध्य प्रदेश के इन्दौर महानगर में दूषित जल पीने से जिस प्रकार 15 लोगों की मृत्यु हुई है वह भारत में बेतरतीब हुए शहरी विकास का भी एक लक्षण है। स्वतन्त्रता के बाद से देश में जिस प्रकार लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है और गांवों में भौतिक विकास की आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी हैं, उसी का परिणाम है कि आज शहरों पर लगातार आबादी का बोझ बढ़ रहा है और इनमें मूलभूत साफ-सफाई से लेकर शुद्ध पेयजल व खाद्य सामग्री का संकट खड़ा हो जाता है। बेशक लोकतन्त्र में लोगों की मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना सरकारों का मुख्य कार्य होता है मगर शहरीकरण के दबाव में इन मूलभूत सुविधाओं की समुचित सुलभता न होना भी असामान्य नहीं होता है क्योंकि जैसे-जैसे इन सुविधाओं का विकास प्रतिवर्ष होता है वैसे-वैसे ही इनकी आबादी में वृद्धि होती जाती है लेकिन इसके बावजूद सरकारें अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती हैं क्योंकि उनकी राजस्व उगाही में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी होती है। शहरों के विकास के लिए और समयानुरूप आधुनिकीकरण के लिए कालान्तर से ही केन्द्र से लेकर राज्य सरकारें विभिन्न परियोजनाएं चलाती रही हैं लेकिन इनकी गति वह नहीं होती जिस गति से इन शहरों की आबादी का विस्तार होता है। मध्य प्रदेश में कुल 16 शहर ऐसे हैं जहां नगर निगम है। इन्हीं में से एक इन्दौर के इलाके भगीरथ पुरा में दूषित जल सप्लाई की वजह से 15 लोगों की मृत्यु हो गई जिनमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। नगर निगम द्वारा सप्लाई किये जा रहे पानी में सीवर लाइन का पानी मिल जाने की वजह से जल दूषित हुआ और इस तरफ स्थानीय निवासियों द्वारा जब विगत अक्तूबर महीने में निगम अधिकारियों से शिकायत की गई तो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। परिणामस्वरूप दिसम्बर महीने के अन्त तक इस समस्या ने भयंकर रूप ले लिया और अपने घरों में लगे नल का पानी पीने से उनकी मृत्यु होने लगी। जब लोग दूषित जल पीने की वजह से बीमार होकर स्थानीय अस्पतालों के चक्कर काटने लगे और वहां से ये खबरें आने लगीं कि बीमार लोगों में से कुछ की मृत्यु का कारण दूषित जल है तो स्थानीय नगर निगम अधिकारियों के कान खड़े हुए और उन्होंने समस्या का संज्ञान लिया। भारत की लोकतान्त्रिक व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रशासनिक प्रणाली केन्द्र, राज्य व स्थानीय निकाय इसीलिए स्थापित की गई थी जिससे इसके नागरिकों को हर स्तर पर जीवन जीने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इन तीनों में स्थानीय निकाय या नगर पालिका की बहुत मूलभूत जिम्मेदारी रहती है। वह सामुदायिक विकास की योजनाओं पर ध्यान देती है और नागरिकों के जीवन-मरण का हिसाब-किताब भी रखती है। नगर निगमों व पालिकाओं का अपना बजट होता है जिन्हें राज्य सरकारें संपोषित करती है। यह बजट नागरिकों की दैनन्दिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बनाया जाता है। इनमें साफ-सफाई का विशेष महत्व होता है। शहरीकरण बढ़ने से इसके हर इलाके में सीवर लाइन बिछाने व पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने को विशेष वरीयता दी जाती है क्योंकि इन दोनों के बिना नागरिकों का जीवन नहीं चल सकता है परन्तु ये दोनों ही कार्य इतनी वैज्ञानिक विशिष्टता के साथ किये जाते हैं कि किसी भी स्तर पर दोनों की लाइनों में प्रवाहित होने वाले जल का मिश्रण न हो सके परन्तु इन्दौर के भगीरथ पुरा इलाके की पेयजल व सीवर लाइनों का पानी आपस में मिल गया जिसकी वजह से भयावह स्थिति पैदा हो गई। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना इन्दौर शहर में पहली बार हुई है क्योंकि भारत के बहुत से महानगरों से ऐसी खबरें पहले भी आती रही हैं मगर इन्दौर नगर निगम के अधिकारियों ने जिस प्रकार से इस बारे में लोगों की शिकायतें मिलने पर नजरंदाजी की उसे अक्षम्य कहा जा सकता है। जाहिर है कि 15 लोगों की दूषित जल पीने से मृत्यु होने के बाद घटना की हुंकार ऊपर तक पहुंचनी लाजिमी थी अतः मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री मोहन यादव का सिंहासन भी डोला और उन्होंने इन्दौर नगर निगम के अपर आयुक्त को निलम्बित करने के साथ अन्य दो बड़े अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इन्दौर नगर निगम पर भी पिछले तीन दशकों से इसी पार्टी का कब्जा है अतः इस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि उसके नेता इस घटना की सीधी जिम्मेदारी लें क्योंकि इससे सीधे भाजपा की प्रशासनिक क्षमता पर सवालिया निशान लगा है और राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस को यह कहने का मौका मिल गया है कि भाजपा में प्रशासन कला की दक्षता नहीं है। इसलिए भाजपा की शीर्ष नेता व राज्य की पूर्व मुख्यमन्त्री सुश्री उमा भारती द्वारा अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना किये जाने को गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता। भगीरथ पुरा इलाके में दूषित पेय जल का प्रकोप किस कदर हुआ, इसका अन्दाजा इसी से हो सकता है कि अभी तक इस क्षेत्र में 13 घरों के 66 हजार लोगों की जांच में उनमें इस जल के कीटाणुओं का प्रकोप पाया गया। अभी भी अस्पतालों में तीन सौ से अधिक लोग गंभीर रूप से इसी वजह से बीमार पड़े हुए हैं। इन्दौर की इस घटना का राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व है क्योंकि भारत के विभिन्न महानगरों में ऐसी समस्या को रोकने के लिए आपातकालीन टीमें तैयार होनी चाहिए और सीवर लाइनों के रखरखाव का परीक्षण निश्चित अन्तराल के बाद होते रहना चाहिए।

बाजार और उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हस्ताक्षर के साथ 'जी राम जी' या 'विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण कार्यक्रम' कानून का रूप लेकर लागू हो चुका है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसके विरुद्ध देशव्यापी विरोध अभियान की घोषणा की है। इस तरह अब राज्यों में मनरेगा की जगह जी राम जी के अंतर्गत योजनाएं चलेंगी, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों का विरोध भी होगा। सामान्य तौर पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार में 2005 में नैशनल रूरल एम्प्लॉयमैंट गारंटी एक्ट या नरेगा कानून लागू किया गया था तो उसका इससे लगाव होगा। किंतु कोई कार्यक्रम बंद नहीं हो और उसकी जगह दूसरा आरंभ न हो सके ऐसी परम्परा न पहले थी और न आगे स्थापित हो सकती है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम बनते हैं तथा उनमें परिवर्तन आने के साथ योजनाएं संशोधित होती हैं, कुछ बंद होती हैं और कुछ बिल्कुल नई आरंभ भी होती हैं। विपक्ष इस कार्यक्रम से महात्मा गांधी नाम हटाने को आधार बनाकर विरोध को एक वैचारिक स्वरूप भी देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यू.पी.ए. सरकार ने भी इसमें महात्मा गांधी का नाम सन् 2009 में जोड़ा था। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि यू.पी.ए. सरकार की महात्मा गांधी के नाम पर अलग से कोई विशेष कार्यक्रम आरंभ करने की सोच नहीं थी, इसलिए पहले से जारी योजना में ही उनका नाम जोड़ दिया गया। विपक्ष की ओर भी उंगली उठती है कि क्या उनका जी राम जी नाम से विरोध है क्या कांग्रेस पार्टी और उन विपक्षी दलों को लगता है कि प्रभु राम का नाम जोड़ने से सरकारी कार्यक्रमों का सैक्युलर चरित्र समाप्त होता है व्यक्तिगत बातचीत में आपको ऐसा करने वाले भी मिल जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से लेकर उनके पुत्र और कांग्रेस के साथी तमिलनाडु के द्रमुक आदि के सनातन और

> **विपक्ष इस कार्यक्रम से महात्मा गांधी नाम हटाने को आधार बनाकर विरोध को एक वैचारिक स्वरूप भी देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यू.पी.ए. सरकार ने भी इसमें महात्मा गांधी का नाम सन् 2009 में जोड़ा था। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि यू.पी.ए. सरकार की महात्मा गांधी के नाम पर अलग से कोई विशेष कार्यक्रम आरंभ करने की सोच नहीं थी, इसलिए पहले से जारी योजना में ही उनका नाम जोड़ दिया गया।**

हिंदुत्व के प्रति विचार और व्यवहार से हम-आप भली-भांति परिचित हैं। नरेगा और मनरेगा को बंद करने या इसमें बदलाव करने की मांग पुरानी है। इस कार्यक्रम ने कागजी खानापूर्ति और भ्रष्टाचार के ऐसे कीर्तिमान बनाए, जिनको किसी सूरत में रोक पाना मनरेगा के ढांचे में संभव नहीं हो पाया। इसके बाद इसके जारी रखने का कोई अर्थ नहीं था। केंद्र से लेकर राज्यों की कैग और अन्य रिपोर्ट, स्वतंत्र एन.जी.ओ. के अध्ययन तथा जमीन स्तर पर साफ दिख रहा था कि मनरेगा के नाम पर ज्यादातर खानापूर्ति हो रही है। किसी कार्यक्रम को बंद करना उस महान व्यक्ति के प्रति धारणा का द्योतक नहीं हो सकता। यह सामान्य समझ की बात है कि 2005 की जिन परिस्थितियों और पृष्ठभूमि में नरेगा आरंभ हुआ, उनमें आज अनेक मायनों में आमूल बदलाव आ गए हैं।

दो दशक पहले नरेगा आरंभ होने के समय की ग्रामीण और समस्त भारत की आर्थिक स्थिति में व्यापक अंतर आ चुका है। 2011-12 में 25.7 प्रतिशत के आसपास गरीब आबादी थी जबकि 2023-24 में यह 4.86 प्रतिशत रह गई है। तब और आज की गांव की स्थिति वैसी ही नहीं है। आज भारत 2047 तक विकसित देश का लक्ष्य बनाकर चल रहा है तो उसमें गांव और शहर से जुड़े सारे कार्यक्रम उस लक्ष्य के अनुरूप होने चाहिए। जी राम जी में 4 मुख्य काम निर्धारित कर दिए गए हैं। जल से संबंधित कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका से संबंधित संरचना और मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले विशेष कार्य। इसमें बाढ़ और सूखे के प्रभावों को कम करने और निपटने के ढांचे भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि जी राम जी का स्वरूप और संस्कार मनरेगा से बिल्कुल अलग है। इस कानून में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित विकसित ग्राम पंचायत योजना को अनिवार्य किया गया है। जैसा हम जानते हैं मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 से ज्यादा जल निकाय बनाए गए हैं या पुनर्जीवित हुए हैं। इसमें खेती और भूजल की स्थिति में परिवर्तन आया है। जाहिर है इसे और शक्ति मिलेगी। जल संचयन बाढ़ निकासी और मृदा संरक्षण आदि काम होंगे तो गांव की आजीविका अपने आप सुरक्षित होगी। इसी तरह सड़कों और संपर्क सुविधाओं के साथ भंडारण, बाजार और उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं बढ़ेंगी तो किसानों के लिए आय के साधन पैदा होंगे। अगर स्थायी टिकाऊ निर्माण हुए और उससे रोजगार के अवसर बढ़े तो पलायन में कमी आएगी। सच कहें तो मनरेगा का नाम सुनकर अनेक किसान रोने लगते थे, गुस्से में आ जाते थे। इस कारण जहां मशीनों की आवश्यकता नहीं थी, वहां भी उनके उपयोग की विवशता पैदा हो गई। बुवाई, कटाई, निकासी आदि के लिए मशीन खरीदना सबके वश की बात भी नहीं रही थी। अब कम से कम रबी और खरीफ के मुख्य मौसम में 60 दिनों तक राज्य मनरेगा को स्थगित कर सकते हैं। इससे खेती के लिए श्रमिकों की उपलब्धता की संभावना बढ़ेगी। कोई भी योजना शाश्वत नहीं हो सकती। अनुभव के आधार पर उनमें संशोधन-परिवर्तन होना चाहिए और जी राम जी भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। भविष्य में परिस्थितियों के अनुरूप इसमें परिवर्तित करने या इसमें संशोधन की स्थिति उत्पन्न होती है तो होगा।

पत्रकार दुश्मन नहीं होता, वो जनता की आवाज बनता है

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के बहुचर्चित मंत्री जी ने माफी मांगी। किसी हद तक माफी बहुत महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य है। नेता हमेशा जनता के सेवक होते हैं और पत्रकार जनता की आवाज। सवाल पूछना उसका हक होता है। जिस दिन सवाल चुप हो जाएंगे उस दिन समझ लो की जनता भी चुप हो जाएगी और अगर पत्रकार नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। पत्रकार दुश्मन नहीं होता, वो जनता की आवाज बनता है। सच्चाई की आवाज होता है। लोकतंत्र की पहचान होता है। पत्रकारों के सवाल लोकतंत्र का मूल हिस्सा हैं। किसी भी नेता को उनके संयम से जवाब देने चाहिए और जवाब देते वक्त शब्दों का चयन भी ठीक से करना चाहिए। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। यह कोई उपमा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब भी सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं तब लोकतंत्र जीवित रहता है। जो सत्ता सवालों को सुन लेती है, वही मजबूत होती है। जब इंदौर में गंदे पानी से लोगों की जान गई। बच्चे मर तो एक पत्रकार अनुराग द्वारी ने वही पूछा जो हर आदमी पूछ रहा था कि यह कैसे हुआ? किसकी जिम्मेदारी, आगे ऐसा न हो, इसके लिए क्या होगा? उसने कोई बदतमीजी नहीं की, न कोई निजी आरोप लगाया। उसने सिर्फ जनता की आवाज उठाई परन्तु उसे जो जवाब मिला, जो शब्द सुनने को मिले और जो अहंकार वाले भाव सामने आए वे न केवल उस पत्रकार को, बल्कि पूरी पत्रकारिता को चुभने वाले थे। कैमरों में कैद यह शब्द देखते-देखते देशभर में चर्चा का विषय बन गया और जब मैंने भी सुना तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। क्योंकि कैलाश वर्गीय जी अश्विनी जी से मिलने कई बार घर आते थे। मुझे तो यही मालूम था बड़े समझदार नेता हैं, क्योंकि मैंने अपने परिवार में सच्ची पत्रकारिता देखी है। लाला जी, रमेश जी, फिर अश्विनी जी को सबको प्रश्न पूछते देखा। अश्विनी जी अटल जी, अडवानी जी, मोदी जी से स्पष्ट सीधे सवाल पूछते थे। कभी किसी ने उल्टा जवाब नहीं दिया। यहां तक अश्विनी जी ने पाकिस्तान में जाकर उनके प्राइममिनिस्टर (पीएम) को सीधे कड़क सवाल पूछे, जिन्हें आज तक लोग याद करते हैं। जब भी राजीव शुक्ला मिलते हैं हमेशा उस बात को दोहराते हैं। मंत्री जी के अपशब्दों और व्यवहार को राष्ट्रीय मीडिया ने गम्भीरता से उठाया। अखबारों, टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया में नाराजगी जताई गई। अंत में मंत्री जी को मीडिया से माफी मांगनी पड़ी, जो मेरी सोच में सही कहा। अगर उनसे गुस्से में या हड़बड़ाहट में गलती हुई है तो माफी बनती है। सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते परन्तु माफी से ज्यादा जरूरी है भविष्य में संयम और सम्मान। पत्रकारों से भी गलती होती है, तो उन्हें कोई अखबार में माफी की लाइन लगाने को कहता है या किसी के बारे में गलत खबर लग जाए तो खेद प्रकट किया जाता है, इसलिए मंत्री जी ने भी अपनी गलती मानकर, माफी मांग कर सुधार किया जो स्वागत योग्य है और नेताओं को भी शिक्षा है, वो जनता के लिए जनता सेवक का उदाहरण बनें। जनता का या पत्रकारों का अपमान न करें। जो पत्रकार ईमानदारी से काम करते हैं तो पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है।

वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली की दिशा में एक निर्णायक कदम

अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य आक्रमण कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करने का दावा किया है। यह अंतरराष्ट्रीय जगत में एक संवेदनशील और ऐतिहासिक घटनाक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई और सैन्य हमले किये हैं। ट्रंप ने कहा है कि मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है तथा देश से निकाल दिया गया है और वे अगली कानूनी प्रक्रिया के लिये अमेरिका ले जाये गये हैं। इस कार्रवाई को ट्रंप ने अपनी योजना के मुताबिक सफल बताया है तथा इसे वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। हालांकि हमले के विवरण और ठोस प्रमाण अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। वहीं वेनेजुएला सरकार ने इसे अमेरिकी सैन्य आक्रमण तथा आंतरिक संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। साथ ही वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गयी है तथा नागरिकों से व्यापक विरोध और प्रतिरोध की अपील की गयी है। इस बीच, विश्व समुदाय के कई देश इस घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ ने इसे कूटनीति की आवश्यकता बताया है जबकि रूस, चीन तथा अन्य ने कड़ी निंदा की है। देखा जाये तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर की गयी सैन्य कार्रवाई तथा एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का दावा विश्व व्यवस्था के लिये एक भयंकर झटका है। यह केवल एक सैन्य और राजनीतिक घटना नहीं है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून, कूटनीति और विश्वशांति के मूल सिद्धांतों पर सीधा प्रहार है। जब किसी देश का नेता बिना संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध, बिना स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय विधिक अधिकरण के निर्देश और बिना अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की सहमति के किसी दूसरे देश में सैन्य हस्तक्षेप कर उसके सर्वोच्च नागरिक नेतृत्व को हटा देता है तो यह कृत्य न केवल उन मूलभूत मानकों का उल्लंघन है जिन पर आधुनिक विश्व राजनीति टिकी हुई है बल्कि यह नए वैश्विक संकटों के लिये एक मिसाल भी स्थापित करता है। पहला सवाल यह है कि क्या ट्रंप का कदम जायज है? क्या ऐसा किसी भी न्यायिक या राजनीतिक मानक पर सही ठहराया जा सकता है? देखा जाये तो संप्रभुता किसी भी वैश्विक समझ का मूल आधार है और किसी भी देश की आंतरिक व्यवस्थाओं के प्रति बाहरी हस्तक्षेप को तभी वैध ठहराया जा सकता है जब वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर व्यापक बहुमत द्वारा अनुमोदित हो या जब प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित मानवाधिकार संकट हो। नरसंहार या बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध की स्थितियों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसी स्वीकृति मिल सकती है लेकिन वेनेजुएला में ऐसे कोई हालात नहीं थे। वेनेजुएला की परिस्थिति चाहे जितनी भी विवादास्पद और जटिल रही हो, अमेरिका का यह एकतरफा सैन्य निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों के सीधे विपरीत है। इसे केवल एक देश के भीतर मानवीय संकट या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के समाधान के रूप में पेश करना नास्तिकता के समान है। ट्रंप प्रशासन के पास यदि मादुरो के खिलाफ वाकई मजबूत सबूत थे तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या किसी बहुपक्षीय मंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये था न कि अपने देश की सैन्य ताकत का उपयोग कर सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए था। दूसरा सवाल यह है कि क्या कूटनीति की दुनिया में इस कदम को उचित कहा जा सकता है? देखा जाये तो कूटनीति वैचारिक मतभेदों, राजनीतिक तनावों तथा सत्ता के संघर्षों को बातचीत, समझौते और मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की कला है। कूटनीति कभी प्रत्यक्ष हिंसात्मक उपायों को प्रोत्साहित नहीं करती। यदि अमेरिका को वास्तव में वेनेजुएला की वर्तमान प्रणाली में विसंगतियाँ और समस्यायें दिखती थीं तो उसके लिये संयुक्त राष्ट्र, ओएएस या किसी अन्य बहुपक्षीय संगठन के साथ मिलकर दबाव बनाना अधिक न्यायोचित और प्रभावी विकल्प होता। इसलिए ट्रंप प्रशासन का यह कदम कूटनीति की भावना का उल्लंघन है और यह उन सभी प्रयासों को भी बेअसर करता है जो शांति, संयम और सामूहिक समाधान की ओर इंगित करते हैं। जब राजनयिक रास्ता खुला रहता है तो हवाई हमले, बमबारी और अस्थिरता फैलाने वाले कदम किसी भी सभ्य कूटनीतिक प्रणाली का अंग नहीं बन सकते। अब तीसरा सवाल यह है कि आगे वेनेजुएला का क्या होगा? देखा जाये तो उस देश का एक अस्थिर भविष्य बेहद संभावित है। हिंसात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप वेनेजुएला के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ और भी भयावह हो सकती हैं। यह देश पहले ही आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति तथा सामाजिक असंतोष का शिकार है, ऐसे में एक बाहरी सैन्य हमले से जनता का मनोबल गिर सकता है, नागरिक प्रतिरोध भड़क सकता है तथा आंतरिक संघर्ष और अधिक गहरा हो सकता है। इसके अलावा यह कदम लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय स्थिरता को भी दहला सकता है और पड़ोसी देशों को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर सकता है। चौथा सवाल अंतरराष्ट्रीय सामरिक प्रभावों से संबंधित है। देखा जाये तो डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति, वैश्विक सामरिक संतुलन पर लंबी अवधि में गंभीर प्रभाव डाल सकती है। ट्रंप द्वारा ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए धमकी देना और अब वेनेजुएला पर प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप जैसे कदम यह संकेत देते हैं कि अमेरिका एक ऐसा वैश्विक प्रहरी बनने की इच्छा रखता है जो अपने हितों को थोपने के लिये सैन्य बल का उपयोग करता है यह विश्व को दोध्रुवीकृत कर सकता है। निश्चित ही यह सब अमेरिका की विरोधी शक्तियों को एकजुट करने का काम करेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बन्सल ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पॉलीटेक्निक एसए. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

लग्जरी कार खरीददारों में ईवी का हो रहा मोहभंग, पारंपरिक इंजन वाले वाहनों की बढ़ रही मांग

नई दिल्ली । देश में जीएसटी बदलावों का असर ऑटो इंडस्ट्री में साफ दिख रहा है। दरअसल लग्जरी कार खरीददारों में ईवी गाड़ियों का मोहभंग हो रहा है और लोग फिर से पारंपरिक इंजन वाली गाड़ियों को खरीद रहे हैं। इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार, जीएसटी 2.0 के दौर में लग्जरी कार सेगमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में तीन फीसदी की गिरावट आई है। इसकी वजह टोटल कोस्ट ऑफ ऑनरशिप को बताया जा रहा है।

जीएसटी दरों में बदलाव का दिखा असर

गाड़ियों के बड़े बाजार में भी पारंपरिक इंजन यानी इंटरनल कम्बशन इंजन की खरीद बढ़ रही है, लेकिन लग्जरी वाहनों में ये बदलाव यादा देखा जा रहा है। बीते साल सितंबर में जीएसटी की दरों में बदलाव हुआ है।

इस बदलाव के तहत 1200 सीसी से कम और 4000 एमएम से कम लंबी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी गाड़ियों और 1500 सीसी की डीजल गाड़ियों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ 1200 सीसी से यादा और 4000 एमएम से लंबी गाड़ियों पर जीएसटी 15-22 प्रतिशत के बीच रखा गया है।

क्या कहते हैं ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गज

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संतोष अय्यर का कहना है, अगर मैं अक्तूबर और नवंबर (2025) को देखूं, तो मध्यम और बजट वाहनों के साथ-साथ लग्जरी सेगमेंट में भी ईवी की बिक्री में 2 से 3 प्रतिशत की गिरावट हुई है, क्योंकि पारंपरिक इंजन वाले वाहनों का ट्रस्ट (टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप) ईवी की तुलना में काफी बेहतर है। इसलिए लोग फिर से पारंपरिक इंजन वाले वाहनों का रुख कर रहे हैं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार ने कहा, जीएसटी 2.0 ने हमारे पारंपरिक इंजन वाले वाहनों के पोर्टफोलियो को और अधिक आकर्षक बनाया है। हम ईवी की मांग में भी मजबूत और लगातार गति देख रहे हैं। आज ग्राहक सिर्फ कीमत से प्रभावित नहीं होते हैं। वे कम संचालन लागत और भविष्य के लिए तैयार टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं।

चावल निर्यातकों की अपील, किसानों की आय व वैश्विक हिस्सेदारी बचाने के लिए पैकेज जरूरी

नई दिल्ली ।

बजट चावल निर्यातकों के संघ आईआरईएफ ने बजट 2026 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को औपचारिक ज्ञापन सौंपा है। संघ ने सरकार से आगामी बजट में बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लक्षित राजकोषीय और नीतिगत उपायों का खाका पेश करने की अपील की है। संघ ने वित्त मंत्री को भेजे अपने ज्ञापन में भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण रोजगार और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भारत के चावल निर्यात के महत्व के बारे में भी बताया। संघ ने अपने पत्र में लिखा चावल क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहा है। (विशेष रूप से प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में भूजल की कमी), खरीद और भंडारण की उच्च राजकोषीय लागत और बाजार/अनुपालन अस्थिरता का सामना कर रहा है। केंद्रीय बजट 2026 लक्षित राजकोषीय और सहायक उपायों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के साथ-साथ स्थिरता और किसानों के लाभों में सुधार कर सकता है। आईआरईएफ ने चावल मूल्य श्रृंखला में स्थिरता, प्रतिस्पर्धात्मकता और किसानों की आय को मजबूत करने के उद्देश्य से प्राथमिकता वाली मांगों को भी वित्त मंत्री से साझा किया है। इसमें पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को कम करने और दीर्घकालिक उत्पादकता में सुधार लाने के लिए जल-बचत और कम उत्सर्जन वाली प्रमाणित पद्धतियों, जैसे कि वैकल्पिक गीलापन और सुखाने (एडब्ल्यूडी), सीधे बोए गए चावल (डीएसआर), लेजर भूमि समतलीकरण और ऊर्जा-कुशल पिसाई से जुड़े कर और निवेश प्रोत्साहन की मांग की गई। उन्होंने किसानों को प्रीमियम बासमती और जीआई-टैग वाले जैविक और विशेष गैर-बासमती चावल की खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन देने का भी आह्वान किया। उनका कहना है कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, बाजार आधारित विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित खरीद पर निर्भरता कम होगी।

क्या आने वाला है बड़ा आर्थिक तूफान? रॉबर्ट कियोसाकी ने दी चौंकाने वाली चेतावनी

बिजनेस डेस्क। मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने नए साल की शुरुआत में ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने दुनिया की आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर बताया है, खासतौर पर चीन की अर्थव्यवस्था को सबसे नाजुक कड़ी करार दिया है। कियोसाकी ने लिखा कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि दुनिया को सिर्फ एक छोटे से इवेंट की जरूरत है, जो पूरी आर्थिक व्यवस्था को हिला सकता है।

उन्होंने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे 1914 में आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने पहला विश्व युद्ध शुरू कर दिया था, वैसे ही आज भी कोई अप्रत्याशित घटना बाजारों को बड़े संकट में डाल सकती है। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब कियोसाकी ने इस तरह की चेतावनी दी हो। वे पिछले एक दशक से लगातार बाजारों में बड़े उतार-चढ़ाव और आर्थिक संकट की आशंका जताते रहे हैं। कियोसाकी का मानना है कि हर आर्थिक संकट सभी के लिए नुकसानदायक नहीं होता। उन्होंने साफ कहा कि मुश्किल वक्त में यादातर लोग गरीब हो जाते हैं, लेकिन जो तैयार रहते हैं, वे और अमीर बनते हैं। यही वजह है कि वे संकट को सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि अवसर भी मानते हैं। उनके अनुसार, बढ़ता वैश्विक कर्ज, राजनीतिक तनाव और कमजोर होती अर्थव्यवस्थाएं हालात को बेहद संवेदनशील बना देती हैं, जहां एक छोटा झटका भी बड़े वित्तीय तूफान में बदल सकता है। हालांकि पोस्ट में उन्होंने कोई ठोस आंकड़े नहीं दिए, लेकिन उनकी बातों का सीधा संबंध आज की वैश्विक चुनौतियों से जुड़ता है–जैसे चीन की सुस्त होती ग्रोथ, दुनिया भर में बढ़ता कर्ज और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव। कियोसाकी की यह पोस्ट भले ही धन्यवाद से शुरू हुई हो लेकिन जल्द ही यह वैश्विक संकट की चेतावनी में बदल गई।

वे लगातार रिटेल निवेशकों को यह सलाह देते रहे हैं कि डर के बजाय तैयारी करें, क्योंकि मुश्किल समय में सस्ती संपत्तियों में निवेश कर बड़ा फायदा कमाया जा सकता है। यही बेबाक सोच उन्हें निवेशकों के बीच इतना लोकप्रिय बनाती है।

घरेलू निवेशकों की मजबूत खरीदारी, वैश्विक संकेतों और एफआईआई से तय होगा इस सप्ताह का रुख

नई दिल्ली । इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल व्यापक आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक रुझानों और विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियों से तय होगी. कारोबारियों ने कहा कि घरेलू संस्थागत निवेशक बिना रुके पूंजी निवेश कर रहे हैं, जिससे पिछले सप्ताह शेयर बाजार में तेजी रही. रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के शोध विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एसवीपी) अजीत मिश्रा ने कहा कि, इस सप्ताह घरेलू और वैश्विक, दोनों स्तरों पर कई आंकड़े आने की उम्मीद है. बाजार कंपनियों के तिमाही नतीजों के शुरुआती चरण में प्रवेश कर रहा है. भारत में निवेशकों की नजर एचएसबीसी सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक (सर्विसेज पीएमआई) और संयुक्त पीएमआई के अंतिम आंकड़ों पर रहेगी. वैश्विक स्तर पर वृद्धि, मांग और मुद्रास्फीति के रुझानों के लिए अमेरिका और चीन के प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी. पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 720.56 अंक या 0.84 प्रतिशत उछला और एनएसई निफ्टी 286.25 अंक या 1.09 प्रतिशत बढ़ा. निफ्टी ने शुक्रवार को 26,340 के अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छुआ. ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, बाजार का ध्यान अब तीसरी तिमाही के नतीजों पर है. निवेशक नतीजों से पहले प्रमुख दिग्गज कंपनियों में चुनिंदा रूप से अपनी पोजीशन बना सकते हैं.

घरेलू स्तर पर, सेवा और संयुक्त पीएमआई के आंकड़े व्यापारिक गति और रोजगार के रुझानों के बारे में जानकारी देंगे. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर ध्यान अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल और बेरोजगारी के आंकड़ों पर रहेगा. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड पर भी इस सप्ताह निवेशकों की नजर रहेगी.

बाजार के स्थिर दायरे में रहने की उम्मीद

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि आने वाले सप्ताह के लिए निवेशक वैश्विक बाजार की दिशा के लिए अमेरिकी पेरोल और बेरोजगारी के आंकड़ों पर ध्यान देंगे. कुल मिलाकर भावना रचनात्मक रहने की उम्मीद है, हालांकि बाजार एक स्थिर दायरे में रह सकते हैं.

सोमवार को बाजार में क्या होगा : सोने में तेजी, रुपया कमजोर, अमेरिका-वेनेजुएला विवाद आखिर कितना असर डालेगा?

नई दिल्ली । 3 जनवरी 2026 को अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंधक बनाने की घटना के बाद पूरी दुनिया की निगाहें सोमवार को सुबह खुलने वाले वैश्विक और भारतीय बाजारों पर टिकी हैं। शनिवार की सुबह जब कराकस में अमेरिकी हवाई हमले हुए, तब तक वैश्विक बाजार सप्ताहांत के लिए बंद हो चुके थे, लेकिन ग्रे मार्केट और सेंटिमेंट ने खतरे की घंटी बजा दी है। अनिश्चितता के इस माहौल में सोना 4,400 प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुका है, जबकि डॉलर की सेफ हेवन मांग के चलते रुपया 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर पर लड़खड़ा रहा है। इस घटना ने न केवल लैटिन अमेरिका में शक्ति संतुलन को बदल दिया है, बल्कि वैश्विक कमोडिटी बाजार, सोने की कीमतों और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। दलाल स्ट्रीट से लेकर कमोडिटी डेस्क तक, हर निवेशक के मन में बस एक ही सवाल है- क्या वेनेजुएला का यह संकट तेल और शेयर बाजार में केवल एक अल्पकालिक झटका साबित होगा, या यह 2026 का पहला वैश्विक तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक परेशान करेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पुष्टि की कि अमेरिकी विशेष बलों ने एक बड़े पैमाने पर हमले को अंजाम दिया है। मुख्य रूप से कराकस स्थित मुख्य सैन्य बेस फुएर्ते तिउना, ला कार्लोटा एयरबेस और ला गुएरा बंदरगाह को निशाना बनाया गया। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर नार्को-टेररिम के आरोप हैं और अमेरिका ने उन पर 50 मिलियन का इनाम रखा था। मादुरो के हटाए जाने के बाद कराकस में अनिश्चितता का माहौल है। उपराष्ट्रपति डेलसी रोड्रिग्ज ने अमेरिका से मादुरो के जीवन के प्रमाण की मांग की है, जबकि रक्षा

मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज़ ने सेना को अलर्ट पर रखा है। दूसरी तरफ, विपक्ष की नेता मारिया कोरीना मचाडो, जिन्होंने ट्रम्प प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया है, ने 100 घंटे और 100 दिन का खाका तैयार किया है। इसमें वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA का निजीकरण और विदेशी निवेश की वापसी शामिल है। अनिश्चितता के इस दौर में निवेशकों ने सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया है, जिससे सोने और चांदी में ऐतिहासिक तेजी देखी गई है। भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते सोना इतिहास में पहली बार 4,400 प्रति औंस के स्तर को पार कर गया है। चांदी भी 75 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और अब सैन्य कार्रवाई ने आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के डार्क फ्लीट (अवैध तेल टैंकरों) पर भी नकेल कसी है। ब्रेंट क्रूड 61 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि वैश्विक बाजार में अभी भी ओवर-सप्लाई (अतिरिक्त आपूर्ति) की स्थिति है, लेकिन वेनेजुएला के भारी क्रूड की कमी जटिल रिफाइनरियों के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। अब 4 जनवरी को होने वाली ओपेक+ की बैठक पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या कार्टेल उत्पादन बढ़ाएगा या मौजूदा कटौती जारी रखेगा? विश्लेषकों का मानना है कि रूस और सऊदी अरब मौजूदा नीति पर कायम रह सकते हैं। भारत के लिए यह संकट दोहरी मार लेकर आया है- ये हैं ऊर्जा सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता। भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट में भारी निवेश है। प्रतिबंधों और अब सत्ता परिवर्तन के कारण ओवीएल का लगभग 600 मिलियन (करीब 5000 करोड़ रुपये) का लाभांश फंस गया है। पुरानी सरकार के साथ हुआ तेल-बदले-लाभांश समझौता अब खटाई में पड़ सकता है। विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय बाजार से निकासी और वैश्विक अस्थिरता के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह भारत के आयात बिल को महंगा करेगा और महंगाई बढ़ा सकता है । भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात, जो 2024 में 111 मिलियन था, भुगतान संकट के कारण बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। 2026 की शुरुआत ने यह साफ कर दिया है कि भू-राजनीति अब अर्थशास्त्र को चला रही है। वेनेजुएला में अराजकता का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उभरते बाजारों की मुद्राओं पर पड़ेगा। शेयर बाजार पर भी सोमवार को इसका असर दिख सकता है। फिलहाल, भारत सरकार ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है, लेकिन ओवीएल के निवेश और गिरते रुपये को संभालने के लिए जल्द ही कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं।

डॉग वाले सर्कुलर को लेकर दिल्ली में सियासत तेज, टीचर पर एफआईआर के बाद आप-बीजेपी में छिड़ा विवाद

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के स्कूल और कॉलेज परिसरों में सुरक्षा को लेकर जारी एक प्रशासनिक सर्कुलर अब शिक्षा का विषय कम और राजनीति का अखाड़ा ज्यादा बनता जा रहा है. आवारा कुत्तों की एंट्री रोकने से जुड़े आदेश पर जहां एक शिक्षक के निलंबन और एफआईआर ने विवाद को हवा दी, वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है. शिक्षा विभाग द्वारा जारी सर्कुलर का मकसद शैक्षणिक परिसरों में छात्रों की सुरक्षा बताया गया, लेकिन आदेश सामने आते ही यह मुद्दा राजनीतिक रंग में रंग गया. सर्कुलर के बाद हुई कार्रवाई ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या असहमति जताना अब अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आदेश पर हो रही आलोचना से सरकार असहज हो गई है. आरोप लगाया गया कि सर्कुलर की समीक्षा करने के बजाय आवाज उठाने वाले शिक्षक को निलंबन का सामना करना पड़ा. आप नेता का कहना है कि शिक्षक ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था, बल्कि केवल प्रशासनिक फैसले पर आपत्ति जताई थी. इसके बावजूद

निलंबन जैसी कार्रवाई यह संकेत देती है कि सरकार आलोचना को सहन करने के मूड में नहीं है. सौरभ भारद्वाज ने एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए सरकार पर चयनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि बीते दिनों जब छात्र संगठन ABVP की नेता द्वारा प्रोफेसर से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, तब सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाया. इससे शिक्षकों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. एफआईआर से डराने की कोशिश, हम पीछे नहीं हटेंगे - आप विधायक आप विधायक कुलदीप कुमार और संजीव झा ने भी प्रेसवार्ता कर सरकार पर निशाना साधा. उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे हथकंडों से डरने वाली नहीं है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि आप नेता तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं. यह बयान उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है. वीरेन्द्र सचदेवा ने स्पष्ट किया कि सर्कुलर में कहीं भी शिक्षकों को आवारा कुत्तों को रोकने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है.

भारत का खेल मॉडल एथलीट-केंद्रित है. एथलीटों के कल्याण को प्राथमिकता : पीएम नरेन्द्र मोदी

वाराणसी।

वाराणसी के सिगरा स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। दोपहर 12 बजे आयोजन में जब पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े तो पूरा स्टेडियम हर-हर महादेव के नारे से गूंज उठा।

वहीं, पीएम मोदी ने नमः पार्वती पतये हर-हर महादेव के जयघोष के साथ स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों, उनके कोच और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने वॉलीबॉल खिलाड़ियों से कहा कि एक कहावत है कि बनारस के जानल चाहत हउआ त बनारस आवे के पड़ी... अब आप सभी बनारस आ गए हैं तो यहां की संस्कृति को भी समझ जाएंगे। आप सभी को यहां उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक मिलेंगे।

वॉलीबॉल हमें टीम फर्स्ट का संदेश देती है, सभी प्लेयर्स अपनी टीम के लिए खेलते हैं। यह खेल हमें सिखाता है कि कोई भी जीत हमारे अकेले की नहीं होती है।

टीम की जीत से सभी जीतते हैं। हमारे देश में भी (इंडिया फर्स्ट) की भावना है। सुबह 11:00 बजे तक सिगरा स्टेडियम में वॉलीबाल खिलाड़ियों के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ता जुट गए थे। इससे पहले, सीएम योगी के आगमन और वर्चुअल रूप से पीएम मोदी को देखने के लिए आतुर भाजपा कार्यकर्ता मोदी-योगी जल्दी आवा व हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। 11:22 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सिगरा स्टेडियम पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

काशी में पहली बार इस तरह के वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश भर से 58 टीमें भाग ले रही हैं। आयोजन के लिए स्टेडियम को रंग-बिरंगे फ्लैग, चैंपियनशिप के बैनर और होर्डिंग से सजाया गया है। 11:15 बजे तक स्टेडियम खिलाड़ियों से भर गया था।

काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ : पीएम मोदी ने किया शुभारंभ, बोले- टीम फर्स्ट का संदेश देता है ये खेल; एक साथ रहें सभी

भाजपा कार्यकर्ता भी जुटे

सीएम योगी ने मंच से पीएम मोदी का आभार कर अपना संबोधन शुरू किया। इससे पहले सीएम योगी का मंच पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और महापौर अशोक तिवारी ने अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इसके बाद वंदे मातरम... गीत गाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर शहर उत्तरी विधायक रवींद्र जायसवाल, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, शहर दक्षिणी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, विधायक टी. राम जिलाध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। 11:40 बजे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पीएम मोदी की काशी में हो रहा है, जिसे पूरा देश देखेगा। आज काशी समेत पूरे देश में खिलाड़ियों की एक अलग पहचान है।

कहा कि आज हमारे देश के खिलाड़ी जब एशियन गेम्स व कॉमन वेल्थ गेम्स में प्रतिभाग करने जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करते हैं, उनके वापस आने पर पीएम मोदी उनसे मुलाकात करते हैं। पहले की सरकार में अपने देश में जब कोई खेल आयोजन होता था तो उसपर भ्रष्टाचार का खेल भी खेला जाता था।

मोदी जी आतंकियों को उठाकर भारत लाओ, आपका 56 इंच का सीना-असदुद्दीन ओवैसी

ट्रम्प वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है तो आप क्यों नहीं

नई दिल्ली।

वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की गूंज अब भारतीय राजनीति में भी सुनाई दे रही है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देश में घुसकर मादुरो को न्यूयॉर्क ला सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी पाकिस्तान जाकर 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस लाना चाहिए। ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा, मोदी जी, आप भी पाकिस्तान जाकर मसूद अजहर और लश्कर के उन शैतानों को वापस ला सकते हैं जिन्होंने मुंबई के खिलाफ साजिश रची थी। ओवैसी के इस तीखे बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने हमेशा आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया, हम एक जिम्मेदार राष्ट्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। भारत अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है और हम किसी के उकसावे में आकर कार्रवाई नहीं करते। खटाना ने जोर देकर कहा कि भारत की रणनीति देशों को नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आतंकवाद के अड्डों को निशाना बनाने की रही है। वहीं, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ओवैसी के बयान पर तंज कसते हुए इसे केवल सनसनी फैलाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ओवैसी अब अमेरिकी राष्ट्रपति को सलाह देने लगे हैं और वे प्रार्थना करते हैं कि ट्रंप उनकी बातों पर विचार करें।

खुद को उम्मीदवार घोषित करने से बचें, विधानसभा चुनाव से पहले केसी वेणुगोपाल की नसीहत

वायनाड। इस साल असम, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इससे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार (04 जनवरी) को पार्टी नेताओं को बड़ी नसीहत दी है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के बारे में खुद घोषणा करने से बचना चाहिए। दरअसल, केसी वेणुगोपाल वायनाड के सुल्तान बाथेरी में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत आयोजित दो दिवसीय नेतृत्व शिविर लक्ष्य 2026 के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। जहां उन्होंने कहा, हमें उम्मीदवारी के बारे में खुद घोषणा नहीं करनी चाहिए। हमें पार्टी के घोषित फैसले का इंतजार करना चाहिए।

चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं की साझा हुंकार; धांधली के लगाए आरोप

'यह लोकतंत्र नहीं, झुंडशाही है'

मुंबई।

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी गठबंधन और चुनावी प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला। इस दौरान दोनों नेताओं ने जल्द ही अपना संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की घोषणा भी की। उद्धव ठाकरे ने कहा अब यह लोकतंत्र नहीं रहा, यह झुंडशाही बन चुका है। पहले वोट चोरी होती थी, अब उम्मीदवार ही चुरा लिए जा रहे हैं। अगर हम रंगे हाथों भी पकड़ लें, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे खुद को पौराणिक उपलब्धियों से जोड़ते हैं, लेकिन वर्षों पहले समुद्र में पूजा करने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा आज तक सामने नहीं आई। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, ताकि सच सामने आ सके।

राहुल नार्वेकर पर गंभीर आरोप

उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का खुलेआम उम्मीदवारों और मतदाताओं को धमकाना बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल नार्वेकर को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। उद्धव ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के बाहर अधिकारियों को नेताओं की सुरक्षा हटाने का निर्देश नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि निर्विरोध उम्मीदवारों को जिताकर मतदाताओं से वोट का अधिकार छीना गया है और ऐसे सभी स्थानों पर उपचुनाव होने चाहिए।

राज ठाकरे का भाजपा पर पलटवार

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में वही पार्टी इस पर चुप क्यों है। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती। जो सोचते हैं कि वे कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगे, उन्हें फिर से सोचना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और बिहार की राह पर ले जाया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। राज ठाकरे ने कहा कि राजनीति में आने वाले लोग अब विचारधाराएं बदलने लगे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।

कश्मीर घाटी में शीतलहर तेज

जम्मू। कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है जिससे पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप और तेज हो गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में शनिवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किये गए तापमान से कम है। उत्तरी कश्मीर का प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग घाटी में सबसे सर्द स्थान बना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि गुलमर्ग में लगातार दूसरी रात न्यूनतम तापमान शून्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं, दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में यह शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। घाटी के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कोकेरनाग में यह शून्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में यह शून्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र इस समय 'चिल्ला-ए-कलां' के दौर से गुजर रहा है। यह 40 दिनों की कड़ाके की ठंड की अवधि होती है और इस दौरान रात का तापमान अक्सर शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है।

त्रिशूर रेलवे स्टेशन पार्किंग एरिया में लगी भीषण आग, 500 गाड़ियां जलकर खाक

त्रिशूर। केरल के अग्निशमन एवं बचाव सेवा के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को त्रिशूर रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में आग भड़क उठी। इस दुर्घटना में लगभग 500 दोपहिया वाहन जलकर राख हो गए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि आग सुबह करीब 6.20 बजे पेड-पार्किंग शेड में लगी और उन्हें 6.40 बजे आपातकालीन सूचना मिली। माना जा रहा है कि बिजली की तार से निकली चिंगारी एक ढके हुए दोपहिया वाहन पर गिरी, जिससे यह हादसा हुआ। अनुमान है कि शेड में करीब 500 वाहन खड़े थे, जिनमें से अधिकतर इसकी चपेट में आ गए। इस दौरान आग बुझाने के लिए दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और सुबह करीब 7.45 बजे तक लपटों पर काबू पा लिया गया। आग को स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए। अधिकारी ने बताया कि जिस जगह आग लगी थी, उसके पास रेलवे ट्रैक पर एक रेल इंजन खड़ा था, लेकिन रेलवे ने उसे किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है। वाहनों के अलावा, टिन की चादरों से बना पूरा शेड भी नष्ट हो गया। पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने आग के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। त्रिशूर पश्चिम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्राथमिकी (एफआईआर) के मुताबिक, 500 वाहनों के साथ-साथ पार्किंग का ठेका चलाने वाली कंपनी अक्षयी एंटरप्राइजेज की रसीद छापने वाली मशीन, कर्मचारियों के दो मोबाइल फोन और 10,000 रुपये नकद भी जल गए।

वाल्मीकि समाज ने एक राष्ट्र एक चुनाव का हस्ताक्षर कर किया समर्थन

चंडीगढ़। वाल्मीकि समाज ने एक राष्ट्र एक चुनाव का हस्ताक्षर कर समर्थन किया है। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक महर्षि वाल्मीकि आश्रम में प्रदेशभर से एकत्र हुए वाल्मीकि समाज के युवाओं ने स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन हस्ताक्षर अभियान के प्रदेश संयोजक कर्ण प्रताप सिंह की अध्यक्षता एवं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी व श्याम सिंह राणा की उपस्थिति में एक राष्ट्र एक चुनाव की मुहिम में हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर बोलते हुए मुहिम के प्रदेश संयोजक कर्ण प्रताप सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में विस्तार से बताया साथ ही इससे देश को होने वाले फायदे भी गिनवाए। उन्होंने अपने

संबोधन में देश में एक ही समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव करवाये जाने से राष्ट्र के समय, संसाधनों के व्यय एवं सुरक्षाबलों की तैनाती जैसे अनेक फायदों पर विस्तारपूर्वक विचार रखे। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी एवं श्याम सिंह राणा ने भी अपने संबोधन में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे गिनवाते हुए इसका समर्थन किया। उन्होंने लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन की टीम को बधाई दी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित वाल्मीकि समाज के युवाओं द्वारा हाथ उठाकर एवं इस अभियान में अपने हस्ताक्षर देकर एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। आज के इस कार्यक्रम में स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रदेश संयोजक कर्ण प्रताप सिंह के अलावा कुरुक्षेत्र लोकसभा के संयोजक रविन्द्र कालवन और जिला संयोजक राहुल गुलिया भी उपस्थित रहे।

हालात चिंताजनक, बातचीत से हो समाधान - भारत

नई दिल्ली। वेनेजुएला में हालिया राजनीतिक और सुरक्षा घटनाक्रम को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा व भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सभी संबंधित पक्षों से अपील करता है कि वे मौजूदा मुद्दों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से संवाद के माध्यम से करें, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी तरह की हिंसा या टकराव से हालात और बिगड़ सकते हैं। वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम भारत के लिए

चिंता का विषय है। भारत सरकार वहां की बदलती स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई के प्रति अपना समर्थन दोहराया है और सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे मुद्दों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से संवाद के जरिए करें, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। काराकास स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करता रहेगा।

'वेनेजुएला पर यूएस एक्शन पर बवाल, 'राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर भारत ने कहा- शांति से सुलझाएं मसला

वेनेजुएला को लेकर भारत की ट्रैवल एडवाइजरी

गौरतलब है कि भारत ने शनिवार रात अपने नागरिकों को वेनेजुएला की स्थिति को देखते हुए वहां गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी। मंत्रालय ने यह परामर्श वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने से जुड़े घटनाक्रम के मद्देनजर जारी किया था। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से भी अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सख्त से सलाह दी जाती है। बयान में कहा गया, जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने, अपनी गतिविधियां सीमित रखने और काराकास स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है।

विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए भारत को आंतरिक तौर पर करना होगा मजबूत, रोहतक में बोले दत्तात्रेय होसबाले

रोहतक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत विश्व का मार्गदर्शन कर सकें, इसके लिए देश को आंतरिक तौर पर मजबूत करना होगा। आंतरिक ताकत देनी होगी और संघ पिछले 100 वर्षों से इसके लिए ही कार्यरत है। उन्होंने कहा कि देश को आंतरिक तौर पर मजबूत करने के लिए समाज की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर आगे आना होगा। सद्भाव के साथ सभी महापुरुषों की जयंती मिलकर मनानी होगी, तभी राष्ट्र मजबूत होगा और जात-पात की खाई को पाटा जा सकेगा। वह रविवार को रोहतक के गोहाना रोड स्थित शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सज्जन शक्ति को समाज परिवर्तन में भूमिका विषय पर आयोजित सामाजिक सद्भाव विचार गोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर क्षेत्र संघचालक पवन जिंदल, क्षेत्र प्रचारक जतिन कुमार, क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य रामेश्वर, क्षेत्र कार्यवाह रोशन लाल, प्रांत संघचालक प्रताप सिंह, प्रचारक डा. सुरेंद्र पाल, कार्यवाह डा. प्रताप सिंह, सहकार्यवाह राकेश, डा. प्रीतम सिंह, प्रचार प्रमुख राजेश कुमार मौजूद रहे। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा

कि भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था, इसलिए भारत ने विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों को भी झेला है। उन्होंने कहा कि 1600 ई में जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई, उस समय भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व्यवस्था में 23 प्रतिशत हिस्सा था। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत आर्थिक तौर पर कितना समृद्ध था। हमारी ज्ञान परंपरा, संस्कृति विश्व के सभी देशों से अच्छी थी, हम समस्त विश्व को एक कुटुम्ब व भारत के सभी धर्मों, परंपराओं, रीति-रिवाजों को अपना मानते हैं। एक चींटी में भी ईश्वर का अंश देखते हैं, लेकिन हम जाति-पाति, भिन्न-भिन्न पंथों में बंट गए और विदेशी आक्रांताओं ने इसका फायदा उठाया और हमें लंबे समय तक गुलामी झेलनी पड़ी। इसका परिणाम यह रहा कि देश की स्वतंत्रता के वर्षों बाद भी हम गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। दत्तात्रेय होसबाले ने कार्यक्रम में समाज के लोगों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि समाज में चिंतन-मंथन होते रहना चाहिए। इससे ही समाज की उन्नति होती है और संघ इसके लिए ही कार्यरत है। इसके अलावा संघ का कोई विशेष एजेंडा नहीं है। उन्होंने नैतिक शिक्षा, गीता व भगवत गीता के एक सवाल के जवाब में कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा सके, धार्मिकता समझाई जा सके, इसके लिए नई शिक्षानीति में प्रयास किए गए हैं, लेकिन वर्षों से जो पाठ्यक्रम हम पढ़ते आ रहे हैं उसको दिमाग से निकलने में समय लगेगा।